

दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना और मदन डेयरी के दूध की कीमतों में वृद्धि

251. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में संचालित मदन डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में बेचे जाने वाले दूध की कीमतों में हाल में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो दूध की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और क्या सरकार इस मूल्य वृद्धि से होने वाले लाभ की राशि को सीधे दूध उत्पादकों को देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो दूध उत्पादकों को दूध के मूल्य में की गई वृद्धि का कितने प्रतिशत हिस्सा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदन डेयरी द्वारा वितरित किये जाने वाले टोण्ड दूध के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः लगभग 11 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है । दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदन डेयरी, दोनों को ही सलाह दी गई है कि वे राज्य सहकारी दुग्ध संघों/राज्य डेयरी संगठनों, जो उन्हें दूध की आपूर्ति कर रहे हैं, के माध्यम से विक्रय मूल्य में की गई वृद्धि का लाभ दुग्ध उत्पादकों को दें ।

उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात

253. श्री बलराम सिंह यादव :

श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उर्वरकों की कमी के बारे में 29 नवम्बर, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 29 "फॉरेक्स क्रच में टिगर फार्म क्राइसिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में उर्वरकों की मांग की अपेक्षा इसकी आपूर्ति के काफी कम रहने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष उर्वरकों की मांग की अपेक्षा इसकी कितनी कमी होने की संभावना है,

(घ) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों के उत्पादन के लिए जितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसका अधिकतर हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे कुल कच्चे माल के कितने प्रतिशत भाग का आयात किया जा रहा है और इस समय जब देश विदेशी मुद्रा के संकट से गुजर रहा है तब इस कच्चे माल को आयात करने के संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ;

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

चालू वर्ष में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। देश में कुल मिलाकर उर्वरकों की बर्तमान होने की संभावना नहीं है। जहाँ तक पोष्टिक उर्वरक का संबंध है, हम पूर्णतया आयातों पर निर्भर हैं, क्योंकि यह अपने देश में उपलब्ध नहीं है। हम कच्चे माल, मध्यवर्ती तथा तैयार उर्वरकों के रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के आयात पर गंभीर रूप से निर्भर हैं। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में यूरिया, जो कि नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है, का आयात नहीं किया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता मुख्यतः स्वदेशी स्रोतों द्वारा पूरी की जा रही है।

दुग्ध उत्पादन

254. श्री बलराम सिंह यादव :

डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दुग्ध के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1951 में देश में दुग्ध का उत्पादन कुल कितना था और वर्ष 1990 के दौरान दुग्ध का उत्पादन कितना रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दुग्ध की अधिकांश मात्रा विक्री हेतु शहरी क्षेत्रों में भेज दी जाती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की दुग्ध खरीदने की क्षमता बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दुग्ध की उत्पादन लागत कम करने के साथ-साथ इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई शिक्षाप्रद उपाय किए हैं जिससे कि ग्रामीण लोगों की दुग्ध खरीदने की क्षमता बढ़ाई जा सके और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1989-90 में अनुमानित अन्तिम दुग्ध उत्पादन 52.4 मिलियन टन था, जबकि 1951 में यह 17.4 मिलियन टन था।

(ग) दुग्ध उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और दुग्ध उत्पादक उपाजन अथवा पुरक आमदनी प्राप्त करने के लिए अपना अतिरिक्त दुग्ध अन्य कृषि उत्पादों की तरह, शहरी बाजारों में बेचते हैं। दुग्ध उत्पादन का वितरण देश में असमान है और एक क्षेत्र में उत्पादित दुग्ध की अतिरिक्त मात्रा बाजारों के विभिन्न चैनलों के जरिये कर्म वाले क्षेत्रों में पहुँचती है।

(घ) ग्रामीणों की क्रय शक्ति शहरी लोगों की तुलना में सामान्यतया कम होती है। प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध की औसत खपत भिन्न-भिन्न होती है जो दुग्ध के स्थानीय उत्पादन, भोजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 42वें सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवार अपने भोजन व्यय का 14.5 प्रतिशत अथवा कुल उपभोक्ता व्यय का 9.5 प्रतिशत दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादों पर व्यय करते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 10.0 प्रतिशत हैं।

(ङ) दुग्ध की उत्पादन लागत को कम करने के लिए आपरेशन प्लड के अंतर्गत कई कदम उठाए गए हैं जैसे दुग्धारू पशुओं में इन्जिन गर्भाधान करके आनुवंशिक सुधार के केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम, संतुलित पशु आहार